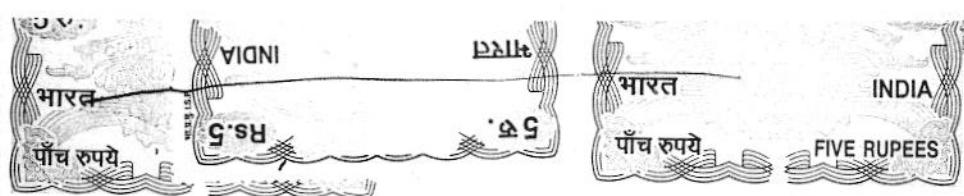


212



ग्रामीण भा. राजस्थान २०३० म.स. रेवाले २५
प्रधानमंत्री । विविध | २०१९-१२/१५५ रु. पुनर्वापन - ७५०/२०१९/६५५५५/२५

कलकत्ता क्रमांक
द्वारा अज दि २७.६.१९
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
क्रमांक १-२-१९ नियम।

कलकत्ता क्रमांक २७.६.१९
राजस्थान नगर नियम

मुख्यमंत्री भाल ३० ग्रामीण भा. सहवापन
आदिवासी निम. ग्राम-नोंदवी कला
तहा/जिल्हा - १५५५५ - आवेदन
७८

म.स. ग्रामीण भा. सहवापन २२.६.१९५५

विविध आवेदन पत्र धारा ४ खं ३२ ग्रा. स. मु. एजेंसी सांस्कृति १९५७
के अन्तर्गत प्रस्तुत विवेदन संदर्भ आदेश राज. राज. अली
पत्र - ३३६। १९ अदिवासी डिग्री - १२।५।१९ वा. पास
श्रीमान् श्री,

विविध आवेदन पत्र पत्र के आधार विषय पक्षा प्रस्तुत है।

- (1) भद्र किं ग्राम कला २२.६.१९५५ के आदेश के विविध
आपूर्वत वा. के आपूर्व प्रस्तुत की के आदेश के विविध
ग्रा. स. मु. एजेंसी २०३० के उपरी आपूर्व प्रस्तुत की जगह प्राप्त
हुए।
- (2) भद्र किं ग्रा. स. श्री श. श. श. श. के आदेश
पत्र-२ की पहली भाइन मे अल्पांग जबलपुर की
जगह अल्पांग २२.६.१९५५ के नियमांश मे आपूर्व
अल्पांग लोगों जबलपुर की आपूर्व २१।५।१९
संग्राम ग्रामीण २१।५।१९ तुटी होने के बारे संशोधित
करने की कामा कर।

मुक्त दिन ०१ दिन ०४
मुक्त दिन ०१ दिन ०४
११।६।१९

नियम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

दिन

आदेश पृष्ठ

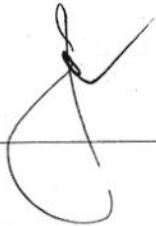
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक पुनर्स्थापन 750/2019/शिवपुरी/भूरा०

मुरारीलाल

विरुद्ध

म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्त्ता एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२-८-२०१९	<p>आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा यह आवेदन म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 एवं 32 के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्य रूप से तर्क किया कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। राजस्व मण्डल के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा 12-4-2019 को आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश में पृष्ठ 2 की पहली पंक्ति में कलेक्टर शिवपुरी की जगह कलेक्टर जबलपुर एवं तीसरी पंक्ति में आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के स्थान पर जबलपुर संभाग जबलपुर टाईप हो गया है अतः इस टाईपिंग त्रुटि को संशोधित किया जाये। इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक ने यह भी अनुरोध किया कि उक्त आदेश विक्य की अनुमति हेतु दिनांक 12-7-2019 तक प्रभावी था जिसे तीन माह बढ़ाये जाये।</p> <p>3/ अनावेदक शासकीय अभिभाषक ने तर्क किया कि विक्य की अनुमति की अवधि पुनर्स्थापन आवेदन में नहीं बढ़ाई जा सकती।</p> <p>4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले से संबंधित है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत मूल अपील प्रकरण क्रमांक शिवपुरी/भूरा०/2019/336 में पारित आदेश दिनांक 12-4-2019 में पृष्ठ 2 की पहली पंक्ति में कलेक्टर शिवपुरी की जगह कलेक्टर जबलपुर एवं पृष्ठ 2 की तीसरी</p>	 

पंकित में आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के स्थान पर जबलपुर संभाग जबलपुर लिपिकीय त्रुटि से टंकित हो गया है। अतः मूल आदेश में पृष्ठ 2 की पहली पंकित में कलेक्टर जबलपुर की जगह कलेक्टर शिवपुरी एवं पृष्ठ 2 की तीसरी पंकित में आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के स्थान पर ग्वालियर संभाग ग्वालियर पढ़े जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जहां तक आवेदक के विक्य अनुमति की समय-सीमा बढ़ाये जाने के तर्क का प्रश्न है म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 में राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस धारा में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिये आवश्यक होने पर ही आदेश देने की राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित किया गया है और उसे अन्यथा प्रभावित करने की अधिकार प्रदान नहीं करती है। इसी प्रकार संहिता की धारा 8 में मण्डल को अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं परन्तु इस पुनर्स्थापन आवेदन में इन दोनों धाराओं का उपयोग कर आवेदक को विक्य की अनुमति की समय-सीमा को बढ़ाये जाने के आदेश दिया जाना उचित नहीं पाता है। जहां विधि में विशिष्ट प्रावधान दिये गये हो तब धारा 32 एवं धारा 8 का प्रयोग किया जाना विधि वर्जित होता है। आवेदक चाहे तो विधि में उपबंधित धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फलस्वरूप आवेदक अभिभाषक यह अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

5/ उपरोक्तानुसार आवेदक के आवेदन का निराकरण किया जाता है। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग होगी। पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(जे0क० जैन)
सदस्य